भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1005
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

केन्द्रीय विद्यालयों में नई स्थानांतरण नीति

†1005. श्री एम. के. राघवनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह देखा है कि केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली नई स्थानांतरण प्रमाण पत्र नीति बच्चों और उनके माता-पिता के मध्यावधि स्थानांतरणों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बच्चों के लिए ऐसी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र नीति के पीछे औचित्य का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई नीति से बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार, रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारी प्रभावित होते हैं जिनका बार-बार स्थानांतरण किया जाता है और जिन्हें अपने बच्चों को उनकी तैनाती के स्थान के नजदीक के स्कूलों में ले जाना पड़ता है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यत देश भर में शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम संचालित करके रक्षा और अर्ध-सैन्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) कर्मियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। वर्तमान में देश भर में 1253 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, के.वि.सं. प्रवेश दिशानिर्देश 2024-25 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिदेश और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) और संबद्धता निकाय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मांग (CBSE) के अनुसार अधिगम परिणामों की प्राप्ति और छात्र-शिक्षक के उचित अनुपात को बनाए रखने के लिए सभी कक्षाओं की छात्र संख्या को फिर से तैयार किया गया है । इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर कक्षा II से VIII के लिए 50 की छात्र संख्या और कक्षा IX से XII के लिए 50 से अधिक छात्र संख्या तक प्रवेश की अनुमति दी गई है।

*****